Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

30-2021/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, FEBRUARY 28, 2021 (PHALGUNA 9, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 28th February, 2021

No. 01-HLA of 2021/6/4193.— The Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 01- HLA of 2021

THE HARYANA RURAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Rural Development Act, 1986.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Rural Development (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 3rd April, 1987.

Amendment of section 6 of Haryana Act 6 of 1986.

2. After sub-section (5) of section 6 of the Haryana Rural Development Act, 1986, the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(5A) The Fund may also be utilized by the Board for payment of pension and other consequential retiral benefits to the employees of the Board.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Pursuant to the decision taken by Haryana Bureau of Public Enterprises (Finance Department) on 26.06.1992 for introduction of Pension Scheme and to comply with the orders dated 08.07.2016 passed by the Hon'ble Punjab and Haryana High Court in C.W.P. No. 3969 of 2012, it is necessary to make an enabling provision in the Haryana Rural Development Act, 1986 to provide pension and consequential retiral benefit to the employees of Haryana Rural Development Fund Administration Board with retrospective effect w.e.f. 3rd April, 1987.

Hence, this Bill.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister,
Haryana.

Chandiarh:
The 28th February, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 1–एच0एल0ए0

हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2021
हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

(2) यह 3 अप्रैल, 1987 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1986 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 6 का संशोधन।

2. हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 6 की उप–धारा (5) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''(5क) बोर्ड द्वारा निधि का उपयोग बोर्ड के कर्मचारियों की पेंशन तथा अन्य पारिणामिक सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है।''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्ट्रप्राइज़ेज़ (वित्त विभाग) द्वारा दिनांक 26.06.1992 को लिए गए निर्णय तथा माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका नं0 3969 ऑफ 2012 में पारित आदेशों दिनांक 8.7.2016 की अनुपालना में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन और इसके फलस्वरूप सेवानिवृत्ति लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात् 3 अप्रैल, 1987 से प्रदान करने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 में समर्थकारी प्रावधान बनाये जाने आवश्यक हैं।

इसलिए, यह विधेयक लाया जाता है।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्य मन्त्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 28 फरवरी, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9083—H.V.S.—H.G.P., Pkl.